the people. Not only the Railways should not remove the narrow-gauge lines but they should not even try to remove a water hut which is once provided. I hope the Railways will not take an absolute narrow materialistic outlook but will first consider the problems of the people. I may also mention here that the State Government has opposed the idea of the removal of the narrow-gauge lines and, I hope, the railway administration will not ignore that opinion.

Now, I would like to refer to one vital point which was also touched upon by the hon. Member, Shri C. C. Desai. It is regarding the construction of Bhavnagar-Tarapur broad-gauge line. This is a very useful and important line not only for Cujarat but for the whole of India. By this line, the western most part of the country will be directly connected with the rest of India on broad-guage. So far as I know, the survey work of this line is over. The Western Railway authorities have finished the survey work, so far as I know. It will not be out of place to mention here that I am constantly pursuing the matter and I am happy to say that the then Railway Minister, Shri C. M. Poonacha, and the Minister of State for Railways, Shri Parimal Ghosh have taken pains to expedite the survey report. Now, I think, it is with the Railway Ministry here. My submission is that, if it is so, the hon. Minister should expedite the matter and finalise the project of Bhavnagar-Tarapur broad-gauge line. I may mention here that the State Covernment have given the top priority to the construction of Bhavnagar-Tarapur project broad-gauge railway lire. Not only that. The State Government had assigned special work to one or two high-raak officials who have furnished all the relevant data regarding the traffic survey. The State Government have forwarded a memorandum and that memorandum gives a correct picture of the economy of the proposed broad-gauge railway line. I hope Dr. Ram Subhag Singh will surely take up this long-pending project and will give due and careful consideration to the demand of the people and the State Government and will finalise the construcion.

Now, the Railway authorities have introduced passenger trains from Halvad to Dhangadhra on Zund Kandla broad-gauge line. But they have not introduced passenger trains beyond Dhangadhra on Dhangadhra Viramgaon section. This has created a terrible inconvenience to the travelling public. The passengers are compelled to change the train at Dhangadhra.

I would like to invite the attention of the Minis;er to the fact that the goods trains are running on that section. Special trains run on this section. Why are only passenger trains not introduced ? Whatever the reason for this may be, the Railways authorities must start passenger trains on this section beyond Dhangadhra without further delay.

Thank you.

SHRIMATI UMA ROY (Malda) : I rise to support the Railway Budget. While agreeing that the diversion of short-distance traffic to road helps in removing congestion in trains, I request you not to be too happy to similar diversion in the case of long-distance passenger-traffic...

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue on the next occasion. Now we have to take up the half-an-hour discussion.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

INDEPENDENCE OF FIJI

श्री कामेश्वर सिंह (खगारिया) : फीजी की स्वतंत्रता का प्रश्न बहुत दिनों से संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान सरदार स्वर्ण सिंह के भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि उन्होंने 12 अक्तूबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया था। उन्होंने उस भाषण में कहा था :

> "In December 1960, the General Assembly adopted the historic Declaration on the granting of Independence to colonial countries and peoples (Resoultion 1654-

[श्री कामेश्वर सिंह]

> (XVI) of the special Committee on Decolonisation with which we have been intimately associated. The discussions in that committee have exposed to the word the appalling conditions that prevail in the remaining colonial territories and it is to the work of the Special Committee that the people in colonial territories have looked for freedom, for hope and for inspiration".

उन्होंने बताया था कि 1960 में यू. एन. की क्या रिकोमेंडेशनज हैं आजादी देने के बारे में। आप देखें कि तब से आज तक भारत सरकार के रिप्रिजेंटेटिव ने वहां पर क्या क्या स्टेप लिये हैं और क्या कहा है। श्री गारे खां ने कहा था कि फीजी यू. एन. का एक डेलीगेशन जाये, फैक्ट फाइंडिंग डैलीगेशन जाए और जो एडमिनिस्ट्रिंग कंट्री है उसकी सहमति से उस डैलीगेशन में मैम्बर लिए जायें। परन्तु ब्रिटेन समय समय पर बराबर इस बात को काटता रहता है और कहता रहा है कि वहां डैलीगेशन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन के डैलीगेट्स ने यहां तक कहा है कि जो भी इनफोर्मेशन चाहिए, जो भी फैक्टस चाहियें उनको दिया जा सकता है, उसको वह वहां दे सकते हैं परन्तु डैलीगेशन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार वहां पर इस प्रश्न को उठाता गया है लेकिन कुछ देश हैं, गिने चुने देश हैं, जैसे अमरीका है, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया है जो या तो वोट नहीं देते हैं या एबसेंट रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस देश को कभी भी स्वतंत्रता दी जाय। मैं ब्रिटेन की लेबर सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि एटलीं साहब ने भारत को आजाद होने में मदद दी थी। इसके मुकाबले में फीजी तो एक बहुत छोटा सा द्वीप है। उसको अगर आजादी दी भी जाती है तो यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी।

बात आजादी देने की ही नहीं हैं। वास्तव में बात यह है कि किसी तरह से पिछड़े हुए देशों को चाहे वे बड़े हों या छोटे, जकड़े रखा जाय। जब कभी सवाल उठता है किसी मुल्क में सफेद चमड़ी वालों का तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे लोगों को फांसी पर लटका दिया जाय या कुछ और भी हो जाय। परन्तु जब दूसरों का सवाल उठता है तो वे लोग इससे पीछे हट जाते है।

मैं आपके सामने एक मजेदार बात रखना चाहता हूं। लंदन में 1965 में एक कान्फ्रेंस हुई थी, कांस्टीट्यूशनल कान्फ्रेंस। 16 अगस्त 1966 को पोलैंड के रिप्रिजेंटेटिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा था :

> "The main issue at London Constitutional Conference in 1965 had not been Fiji's independence but how to create and preserve the inequalities in the representation of various communities in the Legislative Council."

ब्रिटेन के लोग फिजी के 51 प्रतिशत निवासियों को भारतीय कहते हैं। वास्तव में वे लोग भारतीय उत्पत्ति के हैं, लेकिन वे कई पीढ़ियों से वहां रहते आये हैं। फिजी पर अपना प्रभुत्व और साम्राज्य बनाये रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन बराबर यह कहता है कि वे लोग भारतीय हैं, जबकि वे फिजी के निवासी हैं। ब्रिटेन की पालिसी सदा से "डिवाईड एंड रूल" को रही है और वह उस को जारी रखना चाहता है।

हमारे देश के कई डैलीगेशन फिजी गए है। हमारे श्रम मंत्री और विदेश विभाग के सचिव भी अलग अलग डैलीगेशनज में वहां जा चुके हैं। मैं विदेश मंत्री से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यहां से जो भी डैलीगेशन फ़िफी जाते हैं, उनकी रिपोर्ट पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं विदेश मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि ब्रिटेन से बातचीत कर के फिजी में यू. एन. डैलीगेशन भेजने की कोशिश करनी चाहिए । उस डैलीगेशन में भारत के रिप्रिजेंटेटिव, श्री गारेखां, जैसे लोगों को भी सम्मिलित किया जाय, जिन्होंने वहां पर इस प्रश्न को बड़े ज़ोर के साथ उठाया था ।

भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी उस को संसार के किसी भी देश की आजादी के बारे में, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा, चुप नहीं रहना चाहिए । हमारा यह परम् कर्त्तव्य है कि हम संसार के हर एक देश की आजादी के लिए अपनी आवाज उठायें और इस में सम्बद्ध देश की पूरी मदद करें ।

इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा उठाया जाता है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह तय किया है कि 1969 के सत्र में फिज़ी के मामले पर विचार जायेगा । में आपके माध्यम से विदेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि उस सत्र में इस प्रश्न पर भारत का क्या रुख होगा और फ़िज़ी को स्वतंत्रता दिलाने के सम्बन्ध में वहां पर भारन की ओर से क्या कदम उठाये जायेंगे ।

फिज़ी के बारे में हिन्दुस्तान जो कुछ करता है, अंग्रेज लोग उसको कितनी हेय दृष्टि से गिरी हुई दृष्टि से, देखते हैं, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । मि. हैरल्ड हाउटन, डिप्टी एजूकेशन एडवाइज़र इन दि यू. के. डिपार्टमेंट आफ़ टेकनीकल को-आपरेशन, ने सूवा में कहा :

> "He is also reported to have made the remark that some establishments in India were awarding degre:s which he would not regard as the equivalent of good, honest, sixth form work in a secondary in Fiji".

भारत सरकार यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा देने के लिए फ़िजी के विद्यार्थियों को कुछ स्कालरशिप देती है । यह बात अंग्रेजों को नहीं जंचती है । फ़िजी के विद्यार्थी भारत में आ कर रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहां पर स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों को ग्रहण करते हैं । जब वे वापस लौटते हैं, तो वे अपते साथ अपने देश की स्वतंत्रता की उमंग ले कर आते हैं । यह स्वाभाविक है कि वे वहां पर जा कर फ़िज़ी के स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेंगे और इस से ब्रिटेन को कुछ दिक्कत हो सकती है । इसी कारण ब्रिटेन इस बात का विरोध करता है ।

मि० हाउटन के इस वक्तव्य की आलोचना करते हुए **पैसिफ़िक रिव्यू** की ओर से क्या कहा गया, वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं ।

> The Pacific Review said that Mr. Houghton had never been to India to conditions there, nor spent sufficient time to study the local conditions here.

इस से प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान की ओर से फ़िज़ी के विद्यार्थियों को स्कालरशिप दे कर जो अच्छा काम किया जा रहा है, ब्रिट्रेन के मन में उस के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है ।

17 दिम्बर, 1967 को यू० एन० ट्रस्टीशिप कमेटी ने एक यू० एन० मिशन को फ़िज़ी में जाने की इजाज़त न देने के कारण ब्रिटेन की आलोचना की थी ।

इस साल जब संयुक्त राष्ट्र संघ में फ़िजी की स्वतंत्रता का मामला उठाया जायेगा, तो ब्रिटेन, अमरीका और आस्ट्रेलिया की तरफ़ से उस का घोर विरोध किया जायेगा । अब तक वहां पर यह स्थिति रही है कि कभी तीन वोट उन के पक्ष में होते हैं, कभी तीन देश एबस्टेन करते हैं और फ़िजो को स्वतंत्रता देने के पक्ष में कभी 17 और कभी 21 वोट होते हैं ।

[श्री कामेश्वर सिंह]
ब्रिटेन का यह भी एक रिमार्क है यूनाइटेड नेशंस में। यह संयुक्त राष्ट्र वाले कहते हैं :

> "Britain has refused to comply on the ground that the regulations ignored the situation within Fiji where half the people were said to oppose surrendering their colonial status".

अब सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह कहना है कि ब्रिटेन वाले कहते हैं कि फ़िजी में आधे लोग जो हैं वह अपना उपनिवेशवाद का स्टेटस जो है उस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या आप के दिमाग में यह बात कभी आ सकती है कि 1947 में स्वतंत्रता पाने के पहले........

सभापति महोदय : "आप" के माने हैं चेयरमैन से।

श्री कामेश्वर सिंह : जी हां, आप के लिए ही कह रहा हूं। मैं नहीं समझ सकता हूं कि कभी भी 1947 के पहले किसी के दिमाग में ऐसी बात आ सकती थी कि हम लोग स्वतंत्रता नही चाहते हैं? यदि ऐसी बात होती तो 1942 में आन्दोलन नहीं होता। उस के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम की आग यहां नहीं भड़कती। इसी प्रकार फीजी में भी है। उन को दबा कर रखा जा रहा है और कोई भी फैक्ट फाइंडिंग डैलीगेशन वहां जायेगा, बाहर के आदमियों का अधिक आमदरफ्त वहां होगा तो यह जो उन का रिमार्क है, यू० के० का वह गलत साबित होगा। इसलिए बराबर से अंग्रेज यह चाहते हैं कि उस को अलग कर के रखा जाय, उस को बन्द कर के रखा जाय। 1965 में तो स्वर्ण सिंह साहब ने वहां कहा परन्तु उस के बाद वह भी कुछ दिन तक यहां विदेश मंत्री रहे, उस के बाद चागला साहब आये, उस के बाद स्वयं प्रधान मंत्री थीं और उन के बाद अब हमारे नये विदेश मंत्री दिनेश सिंह जी आए हैं, मुझे देखना है कि इतने मंत्री तो निकल गए 1969 तक, अब दिनेश सिंह जी क्या करिश्मा करते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं उम्मीद करता हूं कि यही जाएंगे और पता नहीं क्या कर के आएंगे। इस से पहले मैं इन से कुछ पूछना भी चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि हमारे श्रम मंत्री श्री हाथी जो फीजी गए थे गुडविल मिशन में वहां उन्होंने हर तबके के लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद वह यहां लौटे तो उन्होंने क्या रपट सरकार को दी कि वहां के लोग क्या चाहते हैं? चेयरमैन साहब, मैंने जो आप के सामने ब्रिट्रेन का रिमार्क पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर कि वहां के लोग चाहते हैं कि उपनिवेश ही बना रहे, इस से बहुत गहरा सम्बन्ध यह रखता है। इसलिए मैं विदेश मंत्री से चाहता हूं कि इस बात को वह साफ साफ कहें। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ और लोगों के विचार भी आप के सामने रखता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम बराबर से यह कहते आए हैं खास कर के वह सभी देश जो कि हिन्दुस्तान से इस मामले में कुछ हमदर्दी रखते हैं उन्होंने भी कहा है कि ब्रिट्रेन अपने स्वार्थों के लिए मिलिटरी और एकोनामिक, फीजी को अपने काबू में रखना चाहता है। अब कितना यह राक्षसी विचार उन का है यह तो सोचने की ही बात है।

दूसरी बात यह है और मेरा प्रश्न भी है कि अभी हाल ही में जब कि माइकेल स्टुअर्ट साहब ब्रिटिश फारेन सेक्रेटरी यहां आए थे तो उन से फीजी के ऊपर कुछ बातचीत हुई थी, मैं जानना चाहूंगा विदेश मंत्री से कि माइकेल स्टुअर्ट के साथ क्या बातचीत हुई? मैं अनुरोध करूंगा कि वह जवाबों को टालने की कोशिश न करें। दोनों बातों का साफ साफ जवाब दें और मुझे यह भी देखना है कि 1969 में वह संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करिश्मा करते हैं?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : सभापति महोदय, श्री कामेश्वर सिंह जी ने

जो एक जिक्र किया कि आज वह देश जो स्वतंत्र नहीं हैं उन की स्वतंत्रता के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उन की मदद करनी चाहिए तो मैं नहीं समझता हूं कि इस में कोई दो राय हो सकती हैं।

यह हम सब का कर्तव्य है कि जो कि पहले गुलामी में रह चुके हैं, हम उन देशों की स्वतन्त्रता के लिये पूरी कोशिश करें, जो आज अभी तक स्वतन्त्र नहीं हो पाये हैं और मैं समझता हूं कि भारत का इतिहास इस मामले में एक उज्जवल इतिहास है, जो कोशिशें हम ने अपने साथियों के साथ सब देशों की स्वतन्त्रता के लिये की हैं, वे सब के सामने स्पष्ट हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इस में दो राये नहीं रखेंगे।

आज भी हमारी यही कोशिश है कि फीजी में जल्द से जल्द स्वतन्त्रता आये, वहां के लोग स्वतन्त्र हों और स्वतन्त्र होकर उन के जो मसले हैं, उन को सुलझा सकें, लेकिन हर एक देश की स्थिति कुछ अलग होती है और हम को देखना पड़ता है कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। आज यदि हम खुद कोई फैसला करने की कोशिश करें या हमारे चाहने या सोचने से हम यह समझें कि दूसरा देश उस पर चलने लगे—मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं है। जहां हम दूसरे देशों की स्वतन्त्रता चाहते हैं, वहां हम को इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि वहां के लोग किस तरह से स्वतन्त्रता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। फीजी के लोग स्वतन्त्रता चाहते हैं और बहुत उत्सुकता से स्वतन्त्रता चाहते हैं, लेकिन उन के कुछ मसले हैं, उन मसलों को उन्हें ही तय करना होगा। आज फीजी के लोग, वहां के बड़े बड़े नेता उन मसलों को तय करने में लगे हुए हैं और उन का ख्याल है कि मुमकिन है कि वे उन मसलों को जल्द निबटा सकेंगे और उन मसलों के निबटते ही वे फिर से उनकी जो स्वतन्त्रता की मांग है, उस में लग जायेंगे और हम पूरे तौर से उन की मांग का समर्थन करेंगे और उन की मदद करेंगे। लेकिन जो लोग वहां अपने मामलों को तय करने में लगे हुए हैं, हमें उन को समय देना चाहिये ताकि वे उन पर विचार कर सकें।

पिछली मर्तबा संयुक्त राष्ट्र की जेनरल असेम्ब्ली में भी यह मामला उठा था, वहां भी यही फैसला हुआ था कि फीजी में जो बातें हो रही हैं उन को देखते हुए हमारे लिये बेहतर यही होगा कि इस मसले पर हमारी जो राय है, उस को कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दें...

SHRI RANAGA (Sri Kakulam): What was the stand taken by United Kingdom in the United Nations?

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने यही कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की जनरल असम्बली इस मसले पर गौर करना अभी स्थगित कर दे, क्योंकि वहां पर कुछ बातें चल रही हैं। दूसरे देशों की भी यही राय थी और हम भी उसी राय में रहे, हम ने कोई अलग राय कायम नहीं की। ..

श्री कामेश्वर सिंह : आप यू० के० की राय के हक में थे।

श्री दिनेश सिंह : अगर सब देश यू० के० की राय के हक में थे तो इस का अर्थ यह नहीं है कि उसका नाम यू० के० होने से हम उस से असहमत हो जायें। हम किसी देश के साथ ऐसी भावना नहीं रखते...

श्री कामेश्वर सिंह : उन का रुख देखना पड़ेगा, हमारे साथ वोट देते हैं या नहीं।

श्री दिनेश सिंह : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य दूसरी राय रखते हैं, वह दूसरी राय रख सकते हैं, लेकिन हम उस में शामिल नहीं हैं।

सभापति जी, मैं जिक्र कर रहा था कि वहां पर कुछ बातें चल रही हैं, हर एक को

[श्री दिनेश सिंह]
देखना चाहिये कि इन बातों के क्या नतीजे निकलते हैं उस के बाद हम तय करेंगे कि हम को क्या करना है ।

वहां भी लोगों ने बात-चीत शुरू की और आज हम, उस बात का क्या परिणाम होगा, उसको देख रहे हैं । श्री माइकेल स्टुअर्ट जब भारत आये थे और जब यहां पर भारत सरकार से उनकी वार्ता हुई थी तो उसमें भी फीजी का मामला उठा था......

श्री कामेश्वर सिंह : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर साफ नहीं दिया है । मैं जानना चाहता था कि ब्रिटेन का जो कहना है कि उपनिवशवाद की स्थिति को चाहते हैं तो श्री हाथी जो वहां पर गए थे और उनकी लोगों से बात-चीत हुई तो क्या उनकी राय में ब्रिटेन का कहना सही है है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को क्यों शक है ? कोई भी देश उपनिवेशवाद क्यों चाहेगा ? इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि कोई देश चाहे कि उसके यहां उपनिवेशवाद बना रहे । उस उपनिवेशवाद से स्वतन्त्रता में जाने के रास्ते की बातचीत हो सकती है, लेकिन उपनिवेशवाद बना रहे, यह कैसे कोई चाहेगा ? ताज्जुब की बात है कि इसका कोई जिक्र करने की भी जरुरत हो सकती है ?

SHRI RANGA : They are free in their-own country. They are having self-Government. Is it not ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक इस बात का सवाल है कि श्री माइकेल स्टुअर्ट जब यहां आये थे तो उनसे हमारी क्या बात-चीत हुई, हमने उनसे फीजी के बारे में जिक्र किया और हमने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि वहां शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्रता आये, वहां के लोग मिल-जुल कर रह सकें । उन्होंने भी इस बात को महसूस किया और कहा कि भारत जो इस सम्बन्ध में कर रहा है वह सराहनीय रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर जल्दी स्वतंत्रता आये और मैं समझता हूं अगर इस बातचीत का अच्छा नतीजा निकलता है तो बहुत जल्दी वहां पर स्वतंत्रता आ सकेगी, और अगर अच्छा नतीजा नहीं निकलता है तो क्या हमारी आगे नीति होगी, क्या हम करेंगे वह आज मेरे लिए कहना सम्भव नहीं होगा । मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की और से हम हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जो देश स्वतंत्र नहीं हैं वहां जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता आये ।

श्री रबी राय (पुरी) : सभापति जी, मैं कामेश्वर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आधे घंटे की चर्चा के जरिए उन्होंने फीजी की स्वतंत्रता के बारे में यहां पर सवाल उठाया । मैं निवेदश मंत्री को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि फीजी को आजाद कराने के सिलसिले में, जिस को कि ब्रिटेन गुलाम बना कर रखे हुए है, इनके पास कोई ठोस दृष्टिकोण नहीं है । यूनाइटेड किंगडम ने जिस प्रकार से हिन्दुस्तान में डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी को चलाया, उसी प्रकार से फीजी में भी चला रहा है, इसके सम्बन्ध में एक भारत के प्रतिनिधि, श्री गैरितन ने जो कहा है उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "This policy of the administrative power in Fiji to divide the people on communal and racial lines is nothing new".

हिन्दुस्तान के एक प्रतिनिधि ने स्वयं वहां जाकर इस बात को महसूस किया है कि ब्रिटेन की सरकार फिजी के अन्दर वहा के बाशिन्दों में डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी को चलाती है और उनको पराधीन रखने का कार्य करती है । जिस उज्ज्वलमय इतिहास का जिक्र किया गया कि इंडोनेशिया को लैंड की गुलामी से आजाद करने के लिए हमने पहले की, फीजी को भी आजाद कराने के लिए एशिया और अफरीका के देशों की मदद से ब्रिटेन के खिलाफ यूनाइटेड

नेशन्स में हम जनमत तैयार करें ताकि 1969 में वहां पर जो बहस होने वाली है उसमें कामियाबी मिल सके और फीजी जल्द आजाद हो सके ।

SHRI A SREEDHARAN (Badagara) : Sir, when I heard the hon. minister I thought for a moment whether it was the External Affairs Minister of the U.K. who was speaking here. This question of settling the problem of giving independence is new to us. In India also, Britain trotted out the same claims years ago and only when driven to the wall, they gave us independence. They are repeating the same story in Fiji. When a new External Affairs Minister came, I fervently hoped that he would have a new look at our attitude towards imperialism and colonialism and take an aggressive attitude towards these things. He stated there are certain problems and when those problems are solved, U. K. will willingly give independence to Fiji. that was the indication I gathered. even though he did not say so in so many words. I want to know whether India has taken an assurance from the Government of the U. K. as to who will decide whether these problems are solved. As long as Britain sits in judgment, these problems are not going to be solved, because Britain is a party and deliberately it is engineering that conflict, creating an ugly situations in Fiji. My question is, whether Government have at any time suggested to the U. K. Government that these problems should be settled under the auspices of a word body and not under the auspices of the U. K., because that only Fiji will get independence.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA (Marmagoa) : Two questions arise. One is in the past we were very active and we took a lot of interest in the anti-colonialist movement of the word. There is a feelling current in this country and elsewhere that once we have solved our own problem, and the problem of Goa, Daman and Diu our interest in similar problems elsewhere had waned. May I ask what the hon. Minister proposes to do to ensure that this feelling, which I believe is partly right, is driven away and we continue to have take the same interest in this problem as before.

The second question arises because we Indians are not merely a nationality or a nation, but we are also a race. We find that today from places where we used to settle traditionally like Africa and Persian Gulf, we have been asked to leave from the under-populated areas of the world, to whose development we ean contribute. We are not being allowed to do that, not because we do not have the ability or we cannot centribute to the advancement or the build-up of those countries, but merely because of our race. In these circumstances. may I ask whether the Government plans to make it is responsibility the furtherance of the Indian race and not merely Indian nationality? One of the main reasons as I gather from Press reports why Britain is reluctant to give immediate independence to Fiji is the underlying fact that if independence is granted, the European Minority will lose its dominance and the independent Majority will play its rightful role.

SHRI RANGA : Let us first know whether it is colonialism or imperialism which is sitting on the top of Fiji and whether they have self-government today and they are free except for the name of independence.

SHRI DINESH SINGH : Regarding the question raised by Mr. Rabi Ray whether we are for independence or not, I could not uuderstand why he still carries certain doubts which should have been removed many many years ago. When these years have not removed his doubts, I really do not know whether I would be in a position in the two minutes you have given me even to attempt to remove them. Perhaps. in course of time, when he read more and more of debates in this House he would become conscious of the fact that it has always been our endeavour to fight colonialism wherever it has existed and, may I say, in a constructive manner and not by merely making just vague and general speeches.

The question raised by Shri Sreedharan, whether it was the British Foreign Secretary speaking or the Foreign Minis-

[Shri Dinesh Singh]

ter of India, I would only beg of him to think more in terms of India sitting in Indian Parliament and not think that he is sitting in the House of Commons. If he thinks that he is sitting in Indian Parliament then he will have no doubt that the British Foreign Secretary cannot speak here. The more he thinks of India the more conscious he will become about the policies of India and not the policies talked about by other countries. If he listens quietly to what is said then he will understand and make all these allegations. He did not understand whether it was the British Foreign Secretary speaking or the Indian Foreign Minister speaking only to disturb the proceedings *(Interruptions)*. Yon are aware, Sir, as to what he asked me.

SHRI NAMBIAR (Tirucherppalli) : It is only a phrase. Why should the Minister take the literal meaning of it ?

18 hrs.

SHRI DINESH SINGH : Then may I suggest to the hon. Member that he should be more careful in Picking out the phrases he choses to put before the Indian Parliament. *(Interruption.)* When he talks about our asking the world body to settle the whole case, the fact is that this is before the world body and the United Nations is taking interest. How else does he want us to force the United Nations to take interest when it is before a special committee on colonialism which is considering this matter. I fail to understand what exactly he is trying to tell me to do when we are doing everything possible to assist in the liberation of Fiji.

Shri Sequeira raised rather, if I may say so, an unfortunate interpretation of a very vital question before us. That is the question of the people of Indian origin and he attempted to make out that we should think of Indian race as a nationality. That is vitally against our concept of nationality.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA : I am sorry the the hon. Minister has misunderstood me. I said there was Indian nationality and Indian race.

SHRI DINESH SINGH ; I understood him very well. It is only because I understood him I am trying to answer him. He suggested to me that it should be the responsibility of the Government of India to look after the Welfare of Indian race wherever it exists. That means you are giving a nationality to the people of Indian origin in different countries.

SHRI ERASMO DE SEQUEIRA : I am afraid the Minister has misunderstood. I said that in general where the people of Indian race are being driven out or being kept away from opportunity merely because of their race it should be the responsibility of this Government to raise its voice against it.

SHRI DINESH SINGH : It is our responsibility to protect the interests of Indian nationals wherever they are in the world but it is certainly not our responsibility to interfere in the internal affairs of other countries where people of Indian origin may have acquired another nationality because then, apart from what we may or may not be able to do, they will become suspects in their own country that they do not look for protection to the legitimately constituted government in their country but look for protection to India. It will be an extremely dangerous theory, if I may say so, to propagate at this time when a large number of people of Indian origin are trying to make difficult adjustments to settle in the various countries they are. It has been our endeavour to assist them on humanitarian grounds to find rehabilitation when necessary. We have assisted them on humanitarian grounds when they have been forced to leave the country. But for us to assume a global responsibility of protection on the basis of race and not nationality of a people who have settled in different countries would constitute a tremendous danger for those people themselves who are now trying to make new homes. I would beg of the hon. Member to try to

make a differentiation between our responsibility towards our citizens and our interest in the others on humanitarian grounds. I can assure him that on humanitarian grounds we shall do our best to assist people of Indian origin and, indeed, we have attempted to assist others. But so far as their settlement in a country is concerned it should be a process which has to be attempted by them and in that we should not attempt to interfere *(Interruption)*.

18.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday/ March 5, 1969/Phalguna, 14, 1890.